Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 179-2015] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 8, 2015 (ASVINA 16, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अक्तूबर, 2015

संख्या 11/5/2013–4श्रम.–कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स रेनान इलैक्ट्रिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं0 280, सैक्टर–7, आई0एम0टी0, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात्:–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा न ही उसे अनुमति दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का प्रावधान तथा रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10.00 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की केन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 8th October, 2015

No. 11/5/2013-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of M/s Ryonan Electric India Private Limited, Plot No. 280, Sector-7, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana so as to authorize the employment of woman workers in two shifts between the hours of 7.00 p.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the woman workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the woman workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of woman workers.
8. The shift of woman workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to woman workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the woman workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of woman workers from sexual harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others *Vs* State of Rajasthan *vide* judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour and Employment Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अक्तूबर, 2015

संख्या 11/5/2014–4श्रम.– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स राने एन0एस0के0 स्टीरिंग सिस्टमस प्रा0 लि0, प्लाट नं0 28ए, सैक्टर–6, एच0एस0आई0आई0डी0सी0 ग्रोथ सैन्टर, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात्:–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा न ही उसे अनुमति दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का प्रावधान तथा रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10.00 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की केन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 8th October, 2015

No. 11/5/2014-4Lab.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of M/s Rane NSK Steering Systems Pvt. Ltd. Plot No. 28A, Sector-6, HSIIDC Growth Centre, Bawal, District Rewari, Haryana so as to authorize the employment of woman workers in two shifts between the hours of 7.00 p.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the woman workers in the second shift.

6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the woman workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of woman workers.
8. The shift of woman workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to woman workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the woman workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of woman workers from sexual harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others *Vs* State of Rajasthan *vide* judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour and Employment Department.

HARYANA GOVERNMENT

ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
SECRETARIAT FOR INFORMATION TECHNOLGY

Notification

The 8th October, 2015

No. 2/368/Vol-II/2785.—In order to effectively address Public Grievances relating to installation of Towers and other issues relating to Telecom Infrastructure, the Governor of Haryana is pleased to Constitute State Level Telecom Committee (SLTC) and District Level Telecom Committee (DLTC) in the State.

2. The Constitution of the State Level Telecom Committee shall be as follows:—

Sr. No.	Designation	Position
(i)	Chief Secretary , Haryana	Chairman
(ii)	Administrative Secretary, Revenue	Member
(iii)	Administrative Secretary, Home	Member
(iv)	Administrative Secretary, IT	Member
(v)	Administrative Secretary, PWD(B&R)	Member
(vi)	Administrative Secretary, Health	Member
(vii)	Administrative Secretary, Urban Local Bodies	Member
(viii)	Administrative Secretary, Environment	Member
(ix)	Administrative Secretary, Forest	Member
(x)	Director General of Police	Member
(xi)	Chairman, Pollution Control Board	Member
(xii)	Chief Administrator, HUDA	Member
(xiii)	Managing Director, HARTRON	Member
(xiv)	Joint/Special/Secretary, IT (as case may be)	Convener
(xv)	Deputy Director General (TERM)- Haryana.	Member
(xvi)	State Head of BSNL	Member

(xvii)	State Heads of Telecom/ Infrastructure Provider concerned (against whom complaints are received)	Member
(xviii)	Three eminent public persons (to be nominated by Chairman of SLTC).	Member
(xix)	State Informatics Officer, HSU.	Member

3. **The Role and Responsibilities of SLTC are as under:-**

(i) State Level Telecom Committee (SLTC) shall act as the appellate body of District Level Telecom Committee (DLTC).

(ii) State Level Telecom Committee (SLTC) shall have powers to amend, cancel, endorse the decisions of the District Level Telecom Committee (DLTC) or to remand back to District Telecom Committee for considering a fresh.

(iii) The recommendations of SLTC/DLTC shall be adhered to by concerned ULB/Police Department or any other authority related to the subject.

4. The Constitution of the District Level Telecom Committee shall be as follows:—

Sr. No.	Designation	Position
(i)	Deputy Commissioner of the concerned District.	Chairman
(ii)	Additional Deputy Commissioner	Convener
(iii)	Superintendent of Police	Member
(iv)	Civil Surgeon / CMO	Member
(v)	Executive Engineer, PWD(Roads)	Member
(vi)	Executive Engineer, (Buildings)	Member
(vii)	District Development & Panchayat Officer.	Member
(viii)	Regional Officer, State Pollution Control Board.	Member
(ix)	Assistant Director General, TERM Cell- Haryana.	Member
(x)	District Head of BSNL	Member
(xi)	Divisional Forest Officer	Member
(xii)	District Heads of Telecom/ Infrastructure Provider Concerned. (against whom complaints are received)	Member
(xiii)	Three eminent public persons (to be nominated by Chairman of DLTC)	Member
(xiv)	Representative of ULBs concerned	Member
(xv)	District Informatics Officer/ ADIO, NIC (As case may be)	Member

5. The Role and Responsibilities of DLTC Committees are as under:—

(i) District Level Telecom Committee shall deal with public grievance relating to installation of Mobile towers and other issues relating to Telecom Infrastructure in the respective District.

(ii) District Level Telecom Committee shall initiate *suo moto* actions based on Public protest/ complaint/ petition/press/ media reports etc. in connection with Mobile Tower Installation.

(iii) District Level Telecom Committee shall have powers to send recommendation to ULB or any other authority to cancel the permits granted by ULBs or any other authority for installing Mobile Towers or to issue stop memo if the committee finds:

a. The operator violates Government of India/ State Government guidelines, building rules of ULB or any other authority.

b. Any other institutions involved have given adverse remarks against the Telecom Service Provider (TSP).

(iv) The Committee (DLTC) may give the company (TSP) an opportunity to rectify the defects, if the committee feels so.

(v) Telecom Service Provider or petitioner/complainant may file appeal before State Level Telecom Committee (SLTC) with 15 days from the date of receipt of the DLTC's final decision, under intimation to ULB concerned.

(vi) The recommendations of DTC shall be adhered to by concerned ULB/Police Department or any other authority related to the subject.

(vii) The TSP can also approach DTC for redressing their grievances, if any.

Chandigarh:
The 5th October, 2015.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Electronics & Information Technology Department.

53762—C.S.—H.G.P., Chd.